वर्ष 5, अंक-11, जनवरी-मार्च, 2023

उ. म. शि. अनु. संस्थान
पटना

उद्योग संवाद

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

युवा शक्ति
बिहार की प्रगति

समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों को प्रोत्साहित करते हुए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार।

उद्योग मंत्री जी की कलम से...

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और माननीय उपमुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विजन के अनुसार राज्य में अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि को समर्पित है। उद्योगों की स्थापना के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कोलेटरल सिक्यूरिटी और मार्जिन मनी के समस्या का निराकरण भी इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना के तहत् नए उद्योगों की स्थापना के लिए लाभुकों को प्रति इकाई 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है जिसमें 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में और 50 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में होती है। चार योजनाओं में तीन योजनाओं-मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग योजना तथा मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत् स्वीकृत ऋण ब्याज मुक्त है। जबकि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत स्वीकृत ऋण पर 1 प्रतिशत के ब्याज का प्रावधान है। योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को राशि की विमुक्ति तीन चरणों में :- 4 लाख, 4 लाख और 2 लाख रुपये में की जाती है। सभी चयनित उद्यमियों को उद्यमिता और कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यह बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की फ्लैगशिप योजना है जिसके क्रियान्वयन का दायित्व उद्योग विभाग के कंधो पर है।

हमारी कोशिश है कि इस योजना के तहत् अधिक से अधिक लोगों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया जाए। 2018 से 2021 के बीच मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत् 7098 लोगों को सहायता हेतु चयनित किया गया था, जबकि 2021-22 में 15986 लोगों को इस योजना के तहत् उद्योगों की स्थापना हेतु चयनित किया गया। श्री नीतीश कुमार और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में गठित सरकार इस योजना के लाभ को समाज के सभी वर्गों तक पहुँचाने के लिए संकल्पित है। अब तक 15000 से अधिक नवचयनित उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए प्रथम किस्त की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। 5000 से अधिक उद्यमी दूसरी किस्त भी प्राप्त कर चुके हैं। योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रथम और द्वितीय किस्त की उपयोगिता प्रमाण पत्र ऑनलाईन माध्यम से जमा करने की सुविधा प्रदान की

गई है। कुछ असमाजिक लोग इस योजना के तहत् चयनित लाभुकों को गलत सूचना देकर दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लाभुकों को अपना उद्योग लगाने पर ध्यान देना है और गलत लोगों से दूर रहना है। उद्यमिता की डगर आसान नहीं होती। बहुत मेहनत करना पड़ता है। तब अच्छा परिणाम निकलता है।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत् 2023 में 6930 नये उद्यमियों का चयन किया जा चुका है। इन्हें बेहतरीन प्रशिक्षण संस्थानों में उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण और प्रशिक्षण के उपरान्त प्रथम किस्त की राशि दी जा रही है। तृतीय कैटेगरी के तहत चयनित लाभुकों को बियाडा के प्लग एण्ड प्ले शेड में रियायती दर पर कार्यास्थल उपलब्ध कराने की योजना बनायी जा चुकी है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अब तक 29828 लाभुकों का चयन किया गया है और उन्हें 1910 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार के युवा वर्ग के लिए गेम चेन्जर है। बिहार के अलावा किसी भी अन्य राज्य में उद्यमिता प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। इस योजना के लाभुक पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करें और भविष्य के सफल उद्यमी एवं रोजगारदाता बनें।

समीर कुमार महासेठ

वर्ष 5, अंक-11, जनवरी-मार्च, 2023

उद्योग संवाद
त्रैमासिक

संरक्षक :
समीर कुमार महासेठ
उद्योग मंत्री, बिहार

प्रधान संपादक :
संदीप पौण्डरीक
अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार

संपादक :
दिलीप कुमार
विशेष सचिव, उद्योग विभाग, बिहार

कार्यकारी संपादक :
मनोज कुमार 'बच्चन'
manojkbachchan@gmail.com

संपादकीय संपर्क :
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान
पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पटना–800 013
E-mail : udyogsamvadbihar@gmail.com

प्रिन्ट प्रोडक्शन
ज्ञान गंगा क्रियेशन्स

विषय सूची

- उद्योग मंत्री जी की कलम से 01
- विषय सूची 02
- प्रधान संपादक की कलम से 03
- बी-हब : स्टार्ट अप उद्यमियों के लिए नायाब तोहफा 04
- पटना में बिहार दिवस समारोह 07
- बिहार उत्सव - 2023 : दिल्ली में दिखी बिहार संस्कृति की झलक 08
- मुख्यमंत्री राहत कोष में 13 करोड़ रूपयों का योगदान 09
- बिहार दिवस पर स्कूली बच्चों का औद्योगिक क्षेत्र परिभ्रमण कार्यक्रम 10
- मेडिसाला : हर गांव में डिजिटल डॉक्टर 11
- बिहार एमएसएमई कनेक्ट : 2023 12
- समाधान यात्रा और उद्योग की रफ्तार में तेजी 14
- बिहार कनेक्ट - 23 16
- गणतंत्र दिवस पर उद्योग विभाग की झांकी 17
- राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, बिहार में खड़े होंगे वर्ल्ड क्लस स्टार्ट-अप 18
- नई दिल्ली में आयोजित हुआ बिहार इनवेस्टर कनेक्ट 19
- प्रधानमंत्री गती शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 20
- गुरूनानक नाम इन्टरप्राईजेज 21
- पद्मश्री कपिल देव प्रसाद, बावनबूटी कला से मिली ख्याति 22
- पद्मश्री सुभद्रा देवी, पेपरमेसी कला से मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान 23
- बिहार क्राफ्ट फेयर 24
- मेलो से मिली खादी संस्थाओं को विशेष ताकत 25
- शाजिया क़ैसर : पुराने जूतों को जीवन दान देकर पायी सफलता 26
- फतुहा में बनेगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 27
- हस्तशिल्प कला को सीख रहे युवा 28
- बोलती तस्वीरें 29

इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के हैं
इससे विभाग व सम्पादक-मण्डल का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

प्रधान संपादक की कलम से...

नई सोंच और इनोवेशन पर आधारित नये बिजनेस मॉडल को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार स्टार्ट-अप नीति-2022 बनायी गयी है, जिसमें कम्पनी, साझेदारी या संगठन के रूप में बिहार में प्रारंभ किये गये वैसे संगठनों को प्रोत्साहित करने की योजना है जो नये आइडिया और स्केलेबल व्यापार मॉडल पर आधारित हैं। स्टार्ट-अप के क्षेत्र में बिहार में अपार संभावनाएँ हैं।

राष्ट्रीय स्टार्ट-अप रैंकिंग में बिहार को बड़े राज्यों की श्रेणी में बेहतर इमर्जिंग इको सिस्टम वाला राज्य माना गया है। स्टार्ट-अप के क्षेत्र में बिहार के युवाओं के लिए अपार संभावनाएँ हैं। खुशी की बात है कि बिहार के युवा भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। पिछले छः महीनों में बिहार स्टार्ट-अप नीति के तहत 79 स्टार्ट-अप को 4.01 करोड़ रुपये की राशि विमुक्त की गई।

बिहार के स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने के लिए 10 लाख रूपये के सीड फंड के अलावा एक्सीलेरेशन प्रोग्राम में भागीदारी के लिए 3 लाख रूपये का अनुदान, एन्जेल निवेशकों से निवेश प्राप्त होने पर कुल निवेश का 2 प्रतिशत सफलता अनुदान तथा एन्जेल निवेशकों से प्राप्त फंड के बराबर अधिकतम 50 लाख रूपये तक के मैचिंग लोन की व्यवस्था की गई है। बिहार में स्टार्ट-अप की इको सिस्टम को और बेहतरीन करने के लिए पटना में दो प्रमुख स्थानों पर को-वर्किंग स्पेस, रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट लैब, कॉमन सॉफ्टवेयर एण्ड हार्डवेयर सुविधा, क्वालिटी एश्योरेन्स लैब आदि की व्यवस्था की गई है। साथ ही स्टार्ट-अप को लीगल, एकाउन्टिंग, तकनीकी, पेटेन्ट, निवेश और बैंकिंग सुविधाओं को प्रदान करने की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की गई है।

मौर्यालोक के बी-हब में 500 स्टार्ट-अप को एक छत के नीचे काम करने की सुविधा है। स्टार्ट-अप हब में काम करने के लिए 1500 रूपये के नाम मात्र के मासिक शुल्क पर स्थायी सीट 1000 रूपये के मासिक शुल्क पर फ्लोटिंग सीट और 100 रूपये प्रतिदिन प्रति सीट की दर पर काम करने की आधुनिक सुविधा दी जा रही है। बी-हब द्वारा बिहार की स्टार्ट-अप कम्पनियों को सेबी पंजीकृत कैटेगरी-1 के निवेशक समूहों से फण्ड उपलब्धता हेतु मदद की जाती है। इस हेतु पटना में बिहार कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया जिसमें बिहार के स्टार्ट-अप उद्यमियों को बड़े निवेशकों के सम्पर्क में आने का मौका मिला।

मुझे विश्वास है कि राज्य के युवा बिहार स्टार्ट-अप नीति-2022 में दी जा रही सुविधाओं और मदद का पूरा फायदा उठाते हुए बिहार को स्टार्ट-अप क्षेत्र में आगे ले जाएंगे और राज्य में स्टार्ट-अप का नया इको सिस्टम तैयार होगा।

संदीप पौण्डरीक
प्रधान संपादक
अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार

बी-हब : स्टार्ट-अप उद्यमियों के लिए नायाब तोहफा

युवा सपनों को पंख लगाने तथा उन्हें उड़ान भरने के लिए खुला आसमान देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने बिहार स्टार्ट-अप पॉलिसी 2022 बनायी है। इस नीति के तहत लाभ पाने वाले उद्यमियों को को-वर्किंग स्पेस तथा फैसिलिटेशन सेन्टर की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जिसके मद्देनजर पटना में दो स्थानों-मौर्यालोक और वित्त निगम भवन, फ्रेजर रोड में बी-हब बनाने का निर्णय लिया गया। मौर्यालोक स्थित को-वर्किंग स्पेस तथा फैसिलिटेशन सेन्टर बी-हब शानदार तरीके से विकसित किया गया, जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है।

इस बी-हब का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 08 फरवरी, 2023 को किया। उद्घाटन समारोह में बिहार के मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी, विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव -सह- मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ॰ एस॰ सिद्धार्थ, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक, पटना के जिलाधिकारी श्री चन्द्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक श्री मानवजीत सिंह ढिल्लो, पटना नगर निगम के आयुक्त श्री अनिमेष कुमार पराशर, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह, उद्योग निदेशक श्री पंकज दीक्षित एवं निदेशक हस्तकरघा एवं रेशम श्री विवेक रंजन मैत्रेय भी उपस्थित रहे। उद्घाटन के दिन माननीय मुख्यमंत्री ने स्टार्ट-अप के क्षेत्र में काम कर रहे उद्यमियों से संवाद किया और उन्हें कड़ी मेहनत करते हुए बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए प्रेरित किया।

उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने बिहार स्टार्ट-अप पॉलिसी-2022 के संबंध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पॉलिसी के तहत 10 वर्षों के लिए 10 लाख रूपये तक की ब्याज रहित सीड फंडिंग की व्यवस्था की गई है। महिलाओं द्वारा प्रारंभ स्टार्ट-अप को 5 प्रतिशत, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा दिव्यांगों के स्टार्ट-अप को 15 प्रतिशत अधिक राशि सीड फंड के रूप में देने का प्रावधान किया गया है। एक्सीलेरेशन प्रोग्राम में भागीदारी के लिए 3 लाख रूपये के अनुदान का प्रावधान भी है। एंजेल निवेशकों से निवेश प्राप्त होने पर कुल निवेश का 2 प्रतिशत सफलता शुल्क और सेबी पंजीकृत कैटेगरी 1 तथा एंजेल समूह से प्राप्त फंड के बराबर अधिकतम 50 लाख रूपये तक के मैचिंग लोन की व्यवस्था बिहार स्टार्ट-अप फंड से की जाती है।

कार्यक्रम के दौरान ग्रामश्री किसान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्टार्ट-अप उद्यमी श्रीमती आस्था, शू-रिवाइवल कंपनी की श्रीमती शाजिया कैसर तथा व्यमानिका ऐरो स्पेस के श्री मनीष दीक्षित ने अपनी कंपनी के कार्यों के संबंध में अपने अनुभव साझा किये और बिहार सरकार की स्टार्ट-अप नीति तथा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की

प्रशंसा की।

माननीय मुख्यमंत्री को स्टार्ट-अप उद्यमियों द्वारा तैयार की गयी स्टार्ट-अप किट भेंट की गई। कार्यक्रम में 28 नये स्टार्ट-अप को सीड फंड तथा एक स्टार्ट-अप को मैचिंग लोन कुल 1.78 करोड़ रूपये दिए गए। मुख्यमंत्री ने गोरूरल फूड्स एंड बेवरीजेज प्राइवेट लिमिटेड को 38 लाख 80 हजार 835 रुपये का, यूनिटी डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट एल0एल0पी0 को 5 लाख रुपये का, डिमाया इंफोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड को 6 लाख रुपये का, क्यूरियस बी डिजाईन्स प्राइवेट लिमिटेड को 4 लाख 20 हजार रुपये का तथा मीडिकवाइजर प्राइवेट को 10 लाख रुपये का सांकेतिक चेक सौंपा।

बी-हब में सीटों के आवंटन हेतु बिहार स्टार्ट-अप के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जाता है और सीटों का आवंटन अधिकत्तम 02 वर्ष की अवधि के लिये किया जाता है। बी-हब में स्थायी सीटों का मासिक किराया 1500 रू०, परिवर्तनशील सीटों के लिए मासिक किराया 1000 रू० तथा दैनिक आधार पर 100 रू० प्रतिदिन के आधार पर सीट आवंटित किये जाते हैं।

मौर्यालोक बी-हब में कुल 185 सीटों की व्यवस्था की गयी है। साथ ही एक कॉंफ्रेंस हॉल भी है जिससे लगभग 500 स्टार्ट-अप उद्यमियों को लाभ होगा। स्टार्ट-अप को सहायता देने के लिए बी-हब में फर्नीचर, सी०सी०टी०वी०, वाईफाई कनेक्टिविटी, हाई कैपेसिटी प्रिंटर और कॉंफ्रेंस हॉल की सुविधा प्रदान की गयी है। बी-हब स्टार्ट-अप उद्यमियों को बैंकिंग, निवेश, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पैकेजिंग, मार्केटिंग, चार्टर्ड एकाउटिंग, फायनेन्सियल एनालिस्ट आदि की सुविधा प्रदान करने हेतु तथा बी-हब के संचालन हेतु चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना के साथ एकरारनामा किया गया है।

बिहार के युवाओं को स्टार्ट-अप नीति के बारे में जानकारी देने के लिये विभिन्न कॉलेजों/शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है। ऐसे कार्यक्रम चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना, पटना कॉलेज, ए०एन० कॉलेज, पटना पुस्तक मेला सहित सभी 38 जिलों के पॉलिटेकनिक/तकनीकी संस्थानों में आयोजित किये गये हैं।

स्टार्ट-अप के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था भी बिहार स्टार्ट-अप नीति के तहत की जा रही है। पटना में दो प्रमुख स्थानों पर को-वर्किंग स्पेस, रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट लैब, कॉमन सॉफ्टवेयर एण्ड हार्डवेयर सुविधा, क्वालिटी एश्योरेन्स लैब आदि की व्यवस्था की गई है। साथ ही स्टार्ट-अप को लीगल, एकाउन्टिंग, तकनीकी, पेटेन्ट, निवेश और बैंकिंग सुविधाओं को प्रदान करने की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की गई है।

स्टार्ट-अप के क्षेत्र में अपार संभावनाएँ हैं। यह युवाओं को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। लेकिन स्टार्ट-अप और पारंपरिक व्यवसाय में फर्क होता है। पारंपरिक व्यवसाय के लिए नये आइडिया की आवश्यकता नहीं होती। पहले से चल रहे व्यवसायिक मॉडल पर नया व्यवसाय प्रारंभ करना होता है। पारंपरिक व्यवसाय में तुरंत ही लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन उसके विस्तार की सीमा होती है। उदाहरण के लिए किराना दुकान या आटा चक्की उद्योग के विस्तार की एक सीमा है। लेकिन जब नये आइडिया के साथ स्टार्ट-अप प्रारंभ किया जाता है तो उसके विस्तार की असीम संभावनाएँ होती है।

नये अन्वेषण और नवाचार स्टार्ट-अप के आवश्यक अवयव हैं। पारंपरिक व्यवसाय में अन्वेषण और नवाचार का होना जरूरी नहीं है। स्टार्ट-अप में फोकस लाभ कमाने से अधिक व्यवसाय का विस्तार करने पर होता है। व्यवसाय के विस्तार के बाद एन्जेल इन्वेस्टर्स से निवेश की संभावना बढ़ जाती है और वैसी स्थिति में स्टार्ट-अप को बड़ा लाभ प्राप्त होता है।

बिहार में ज्यादा से ज्यादा स्टार्ट-अप प्रारंभ हो इसके लिए उद्योग विभाग लगातार पहल कर रहा है। राज्य के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में स्टार्ट-अप के प्रति जागरूकता के लिए आउटरीच कार्यक्रम चलाये गए हैं जिनमें युवाओं के साथ सीधा संवाद स्थापित करते हुए उन्हें बिहार स्टार्ट-अप नीति की प्रमुख बातों से अवगत कराया गया। स्टार्ट-अप फंडिंग के लिए लाभुकों के चयन की पारदर्शी प्रक्रिया बनायी गई है।

स्टार्ट-अप पोर्टल पर आवेदन करने वाले आवेदकों के आवेदनों की पूरी जाँच के बाद वरिष्ठ अधिकारियों की टीम द्वारा उनकी पुनर्जांच की जाती है और फिर सीड फंड स्वीकृत किया जाता है। बिहार स्टार्ट-अप नीति के तहत लाभ लेने वाले स्टार्ट-अप केन्द्र सरकार की दूसरी एजेन्सियों से लाभ प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होते हैं।

उद्योग विभाग के प्रयासों से बिहार में स्टार्ट-अप का माहौल बन चुका है। केन्द्र सरकार की स्टार्ट-अप सनराइजर्स रैंकिंग में इमर्जिंग स्टार्ट-अप इको सिस्टम के कैटेगरी-'ए' में बिहार को टॉप पोजिशन पर रखा गया है। यह विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के सतत प्रयास और सबके सहयोग से ही संभव हो पाया है।

बिहार स्टार्ट-अप नीति के तहत 2017-22 तक 145 इकाईयों को सीड फण्ड का लाभ मिला। नई स्टार्ट-अप नीति के तहत पिछले चार महिनों में 76 लोगों को स्टार्ट-अप के रूप में चिन्हित किया गया है और उन्हें सीड फण्ड दिया जा चुका है।

हमारी कामना है कि बिहार का स्टार्ट-अप यूनिकॉर्न बने। बिहार स्टार्ट-अप नीति के तहत एंजेल इन्भेस्टर से निवेश प्राप्त होने पर बिहार सरकार की ओर से पचास लाख रूपये का मैचिंग लोन प्रदान किया जायेगा। उसे पाने की कोशिश करें। बिहार में कई स्टार्ट-अप अच्छा काम कर रहे हैं। जिसमें सत्तूज, ग्रामश्री एग्री सर्विसेज, एग्री फीडर, एग्रीक्श एग्रोटेक आदि शामिल है।

पटना में बिहार दिवस समारोह

उद्योग मंडप में स्टार्टअप और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों ने किया सबको प्रेरित

बिहार राज्य की स्थापना के 111वें साल पूरा होने की खुशी में बिहार दिवस का आयोजन पूरे राज्य में किया गया। मुख्य कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किया। बिहार दिवस समारोह में अनेक विभागों की सक्रिय भागीदारी रही। उद्योग विभाग की ओर से लगाए गए उद्योग मंडप में करीब 100 उद्यमियों को अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री का अवसर मिला।

उद्योग विभाग से जुड़े 18 उद्यमियों को पवेलियन ए में अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री का अवसर प्रदान किया गया। उद्योग मंडल में इस बार मुख्य फोकस बिहार स्टार्टअप और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों पर रहा। प्रदर्शनी में शामिल उद्यमियों में लगभग आधी भागीदारी इन योजनाओं के लाभुकों की रही। जीवंत प्रदर्शनी तथा स्टार्टअप इकाई द्वारा ड्रोन के प्रदर्शन के बल पर उद्योग मंडप पहले दिन से ही आकर्षण का केंद्र बन गया। बिहार दिवस समारोह के दूसरे दिन उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ गांधी मैदान आए।

उद्योग मंत्री ने विभाग के पवेलियन में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना तथा बिहार स्टार्टअप के साथ सभी उद्यमियों की हौसला अफजाई की। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि बिहार अपनी स्थापना का 111वीं वर्षगांठ मना रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार वंदन की भूमि है, बिहार अभिनंदन की भूमि है। बिहार का अतीत गौरवशाली है और भविष्य सुनहरा। बिहार भगवान महावीर, गौतम बुद्ध और गुरु गोविंद सिंह की धरती है। बिहार का सांप्रदायिक सौहार्द अप्रतिम है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार विकास और समृद्धि की नई गाथा लिखने के लिए भी तत्पर है। जल-जीवन-हरियाली, हर घर नल का शुद्ध जल और बालिका पढ़ाओ जैसी योजनाओं में बिहार ने देश को दिशा दी है। बिहार राज्य को औद्योगिक निवेश के लिए सबसे उपयुक्त जगह बताते हुए समीर कुमार महासेठ ने कहा कि बेहतरीन आधारभूत संरचना, समाज के हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजना और उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं ने पूरे देश का ध्यान बिहार की ओर आकृष्ट किया है।

बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 1400 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए उद्योग विभाग की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत करीब 29000 युवाओं को 1450 करोड़ की राशि बिहार सरकार ने उपलब्ध कराई है। बिहार सरकार की मदद से ये युवा उद्यमी एक दिन बड़े होते ही बनेंगे ऐसा हमारा विश्वास है।

बिहार की प्रगति में युवा शक्ति का अहम योगदान रहेगा। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हम मार्गदर्शन से लेकर मार्केटिंग तक के मामले में उनकी सहायता कर रहे हैं। बिहार की स्टार्टअप नीति के बारे में बताते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि स्टार्टर उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत सीडफंड, मैचिंग लोन और कॉमन वर्किंग स्पेस जैसी सुविधाएं बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। स्टार्टअप उद्यमियों के लिए पटना में दो स्थानों पर बनाया गया बी-हब कॉमन वर्किंग स्पेस सह मोटिवेशन सेंटर अपने आप में अद्वितीय है जहां पर स्टार्टअप इकाइयों को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जा रही है।

उद्योग मंत्री ने विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी सह बिक्री कार्यक्रम के प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। उद्योग विभाग की प्रदर्शनी में तीसरे दिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह और उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक आए। उद्योग मंडप में उद्यमियों के उत्साह को देखते हुए उद्योग मेला के समय को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया। बिहार दिवस मनाने के क्रम में ऐसा पहली बार हुआ जब उद्योग मेला के समय को 3 दिन से बढ़ाकर 10 दिन तक कर दिया गया। ◉

बिहार उत्सव-2023
दिल्ली में दिखी बिहारी संस्कृति की झलक

उद्योग विभाग द्वारा बिहार के हस्तशिल्प,लोककला, हथकरघा, स्टार्टअप और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई दिल्ली के आई एन ए दिल्ली हाट में 16 मार्च 31 मार्च के बीच आयोजित बिहार उत्सव 2023 के बीच बिहार उत्सव 2023 का आयोजन किया गया।

उद्योग विभाग द्वारा बिहार के हस्तशिल्प,लोककला, हथकरघा, स्टार्टअप और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नई दिल्ली के आई एन ए दिल्ली हाट में 16 मार्च 31 मार्च के बीच आयोजित बिहार उत्सव 2023 के बीच बिहार उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। आयोजन में दिल्ली हाट परिसर में आवंटित 120 स्टॉलों पर बिहार के 128 उद्यमियों ने अपने उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री की। प्रतिदिन 15 लाख रुपए से अधिक मूल्य के सामानों की बिक्री से यह साबित हो गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बिहार के उत्पादों की बहुत ही अच्छी मांग है।

बिहार उत्सव के आयोजन के क्रम में तीन दिवसीय बिहार दिवस समारोह का आयोजन 21 मार्च से 23 मार्च के बीच किया गया। बिहार दिवस समारोह का उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किया। उद्घाटन समारोह में उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौण्डरीक और दिल्ली में बिहार के स्थानिक आयुक्त कुंदन कुमार अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह में उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि बिहार वंदन की भूमि है,बिहार अभिनंदन की भूमि है।

बिहार का अतीत गौरवशाली है और भविष्य सुनहरा। बिहार भगवान महावीर, गौतम बुद्ध और गुरु गोविंद सिंह की धरती है। बिहार का सांप्रदायिक सौहार्द अप्रतिम है। उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार विकास और समृद्धि की नई गाथा लिखने के लिए भी तत्पर है। जल-जीवन-हरियाली, हर घर नल का शुद्ध जल और बालिका पढ़ाओ जैसी योजनाओं में बिहार ने देश को दिशा दी है।

बिहार राज्य को औद्योगिक निवेश के लिए सबसे उपयुक्त जगह बताते हुए समीर कुमार महासेठ ने कहा कि बेहतरीन आधारभूत संरचना, समाज के हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजना और उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं ने पूरे देश का ध्यान बिहार की ओर आकृष्ट किया है। बिहार के औद्योगिक क्षेत्रें के विकास के लिए 1400 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए उद्योग विभाग की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत करीब 29000 युवाओं को 1450 करोड़ की राशि बिहार सरकार ने उपलब्ध कराई है। बिहार सरकार की मदद से ये युवा उद्यमी एक दिन बड़े होते ही बनेंगे ऐसा हमारा विश्वास है।

बिहार की प्रगति में युवा शक्ति का अहम योगदान रहेगा। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हम मार्गदर्शन से लेकर मार्केटिंग तक के मामले में उनकी सहायता कर रहे हैं। बिहार की स्टार्टअप नीति के बारे में बताते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि स्टार्टर उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के तहत सीडफंड, मैचिंग लोन और कॉमन वर्किंग स्पेस जैसी सुविधाएं बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। स्टार्टअप उद्यमियों के लिए पटना में दो स्थानों पर बनाया गया बी-हब कॉमन वर्किंग स्पेस सह मोटिवेशन सेंटर अपने आप में अद्वितीय है जहां पर स्टार्टअप इकाइयों को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जा रही है।

मैथिली ठाकुर के गीतों पर झूमे श्रोता

बिहार दिवस समारोह के पहले दिन दिल्ली हाट में बिहार की सुप्रसिद्ध लोक गायिका सुश्री मैथिली ठाकुर का गायन कार्यक्रम हुआ। मैथिली ठाकुर ने बिहार के पारंपरिक लोकगीतों की शानदार प्रस्तुति दी। उन्होंने राम सीता विवाह प्रसंग सीता जी के जन्म के प्रसंग पर आधारित कई गीतों की प्रस्तुति दी। बिहार के पारंपरिक गीतों पर भी लोग झूमते नजर आए। मैथिली ठाकुर ने आजु मिथिला नगरिया निहाल सखिया,चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी बता द बबुआ, सिया जी बहिनिया हमार हो जैसे गीत गाए। बिहार दिवस समारोह के दूसरे दिन वरिष्ठ संगीतकार अर्जुन चौधरी के नेतृत्व में दर्जनभर वरिष्ठ संगीतकारों की टीम ने रिदम आफ बिहार प्रस्तुत किया। इसी दिन मां तारा संगीत कला केंद्र के लोक कलाकारों ने बिहार के अलग-अलग शैली के लोक नृत्यों की प्रस्तुति करते उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। समारोह के तीसरे दिन सुरांगन कला संस्थान के कलाकारों ने लोक नृत्य और वरिष्ठ गायक स्वतंत्र कुमार संगीत ने लोक गीतों की प्रस्तुति दी।

सम्मानित किए गए कपिल देव प्रसाद और सुभद्रा देवी

वर्ष 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए दो कलाकार श्री कपिल देव प्रसाद और श्रीमती सुभद्रा देवी को दिल्ली उत्सव में उद्योग मंत्री ने विशेष तौर पर सम्मानित किया। बावन बूटी हस्तशिल्प कला के कलाकार

कपिल देव प्रसाद और पेपर मेसी की अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार सुभद्रा देवी को उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने लोक गायिका मैथिली ठाकुर को भी बिहार दिवस का स्मृति चिन्ह प्रदान किया।

:: सोनू कुमार

मुख्यमंत्री राहत कोष में 13 करोड़ रुपयों का योगदान

मुख्यमंत्री सचिवालय के लोक संवाद कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को बिहार के उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ और उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने उद्योग विभाग की दो संस्थाओं की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में 13 करोड़ रुपयों का चेक सौंपा। बिहार राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकार की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में 11 करोड़ रुपए तथा आधारभूत संरचना प्राधिकार की ओर से दो करोड़ रुपए का योगदान मुख्यमंत्री राहत कोष में किया गया।

बिहार दिवस पर स्कूली बच्चों का औद्योगिक क्षेत्र
परिभ्रमण कार्यक्रम

युवा शक्ति ही बिहार की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने में सक्षम है। युवाओं को सरकारी नौकरी की मानसिकता से बाहर निकालकर उद्यमिता की राह पर आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार दिवस-2023 के दौरान शिक्षा विभाग और उद्योग विभाग ने मिलकर अभिनव पहल किया। राज्य के सभी 38 जिलों के कुल 160 औद्योगिक इकाइयों में स्कूल छात्र-छात्राओं के भ्रमण का कार्यक्रम बनाया गया।

युवा शक्ति ही बिहार की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने में सक्षम है। युवाओं को सरकारी नौकरी की मानसिकता से बाहर निकालकर उद्यमिता की राह पर आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार दिवस-2023 के दौरान शिक्षा विभाग और उद्योग विभाग ने मिलकर अभिनव पहल किया। राज्य के सभी 38 जिलों के कुल 160 औद्योगिक इकाइयों में स्कूल छात्र-छात्राओं के भ्रमण का कार्यक्रम बनाया गया। 22 मार्च से 24 मार्च 2023 के बीच कुल 4790 विद्यार्थियों ने औद्योगिक क्षेत्रों का भ्रमण किया और उद्योगों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। जो बच्चे औद्योगिक क्षेत्रों में गये, उनमें से अधिकतर ने कभी भी बड़ा उद्योग चलते नहीं देखा था। उद्योगों के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा था। औद्योगिक परिभ्रमण के दौरान बच्चों को उद्योग लगाने और उद्योग चलाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उद्योग चलाने के लिए भूमि, पूंजी, श्रम और प्रबंधन की सम्मिलित भूमिका होती है। नये दौर में मार्केटिंग और ब्रांडिंग की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गयी है। औद्योगिक क्षेत्र परिभ्रमण के दौरान बच्चों ने उद्योग चलाने के इन विभिन्न अवयवों को जाना।

औद्योगिक परिभ्रमण के लिए कक्षा-7 से कक्षा -10 तक के बच्चों को ले जाया गया। उद्योग विभाग ने बच्चों की अभिरूचि को देखते हुए हर तरह की औद्योगिक इकाइयों में परिभ्रमण कराया। दरभंगा जिले में बच्चे मुर्गी दाना और कुरकुरे चिप्स की फैक्ट्री देखने गये तो कटिहार जिला के बच्चे मनसा जूट मिल गये जहाँ उन्होंने जूट प्रोसेसिंग के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। कैमूर जिला के बच्चे औद्योगिक परिभ्रमण के लिए रूचि सोया इन्डस्ट्रीज लि. में गये जहाँ उन्हें बिस्कुट निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। वैशाली और सिवान जिला के बच्चें को अनमोल कम्पनी के बिस्कुट और नमकीन फैक्ट्री में ले जाया गया और उन्हें फूड प्रोसेसिंग के बारे मे जानकारी दिया गया। इसी तरह बेगूसराय जिला में बच्चों को वरूण बेवरिज ले जाया गया जहाँ उन्हें बोतल बंद पेय पदार्थों की पैकेजिंग प्रक्रिया को जाना। बिहार प्रांत में कृषि उत्पाद आधारित उद्योगों के विकास की भरपूर संभावनाएँ हैं। इस आलोक में मुंगेर जिला में बच्चों को दीपा मशाला उद्योग, अरवल जिला में भदासी राईस, बेगूसराय जिला में कृष्णा राईस, बक्सर जिला में सिद्धाश्रम राईस और दरभंगा जिला में सिंह चूड़ा सत्तू उद्योग ले जाया गया।

चनपटिया स्टार्ट-अप जोन की सफलता पूरे देश में एक नजीर बनी है। पश्चिम चम्पारण जिला के स्कूली बच्चों ने चनपटिया स्टार्ट-अप जोन में लगायी गयी इकाइयों का परिभ्रमण कर लघु उद्योगों के इकाइयों के प्रक्रिया को देखा और समझा।

औद्योगिक परिभ्रमण के दौरान स्कूली बालक-बालिकाओं को औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना-मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और बिहार स्टार्ट-अप के संबंध में बच्चों ने अधिक दिलचस्पी दिखाई। उन्हें बताया गया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चार उप योजनाएँ चलायी जाती हैं। जिसके तहत प्रत्येक लाभुक को 10 लाख रूपये तक की सहायता दी जाती है। जिसमें 5 लाख रूपये ऋण के रूप में और 5 लाख रूपये

अनुदान के रूप में दी जाती है। बिहार स्टार्ट-अप नीति के तहत चयनित स्टार्ट-अप इकाइयों को 10 लाख रूपये तक का सीड फंड दिया जाता है। इसके अलावा एन्जेल इन्वेस्टर्स से निवेश प्राप्त होने पर उन्हें 50 लाख रूपये तक का मैचिंग लोन भी दिया जाता है। एक्सीलेरेशन प्रोग्राम में भाग लेने के लिए स्टार्ट-अप को 3 लाख रूपये तक की सहायता दी जाती है। औद्योगिक परिभ्रमण के दौरान स्टार्ट-अप के लिए कॉमन फैसिलिटी सेन्टर बी-हब के बारे में भी जानकारी दी गई जहाँ स्टार्ट-अप उद्यमियों को को-वर्किंग स्पेस, आर.एन.डी. लैब, कॉन्फ्रेंस रूम, साझा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, कॉमन टेस्टिंग लैब और टूल रूम, कानूनी, लेखा, प्रौद्योगिकी, पेटेन्ट, निवेश और बैंकिंग की साझा सुविधाएँ और इनक्यूबेशन फैसिलिटी दी गई है।

औद्योगिक परिभ्रमण कार्यक्रम के तहत उद्योगों का भ्रमण करने वाले बच्चों का अनुभव सकारात्मक रहा और कई बच्चों ने बड़ा होकर उद्योगों की स्थापना कर अपने लिए रोजगार का प्रबंध करने के साथ-साथ दूसरों को भी रोजगार देने की बात कही। ◉

मेडिशाला

हर गांव में डिजिटल डॉक्टर

मो. अमानुल्लाह, रितुराज स्वामी, सुमन सौरव और प्रिन्स कुमार बिड़ला इन्स्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बी.टेक कर रहे थे तो अपनी पढ़ाई तीसरे साल में चारों ने मिलकर एक ख्वाब देखा। आगे नौकरी नहीं करनी है। बल्कि कुछ ऐसा करना है जिससे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का भला हो सके।

कैम्पस सेलेक्शन के दौरान चारों के पास कुछ अच्छे ऑफर भी आए लेकिन चारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था के सुधार के प्रोजेक्ट पर काम करने लगे। ग्रेजुएशन करने के बाद चारो ने मिलकर मेडिशाला हेल्थकेयर प्रा0 लि0 की शुरूआत की। जिसके तहत उन्होंने गांवों में डिजिटल क्लीनिक खोलकर शहर में रहने वाले डॉक्टरों की सुविधा इलेक्ट्रोनिक माध्यम से देना प्रारंभ किया।

इस तरह जिन गांवों में कम्पनी की ओर से सेहत, डिजिटल क्लीनिक खोला गया, वहां करीब 350 डॉक्टरों की कन्सलटेन्सी सेवा उपलब्ध हो गई। मो0 अमानुल्लाह कहते हैं कि उनकी कम्पनी के काम करने का तरीका बहुत ही सरल है। गांव के डिजिटल क्लीनिक पर दो प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहते हैं। डिजिटल क्लीनिक पर आने वाले मरीजों की प्रारंभिक जांच वही दोनो करते हैं उसके मरीज से संबंधित डाटा को फीड कर दिया जाता है और फिर आवश्यकतानुसार टेलीमेडिसीन द्वारा शहरी क्षेत्र में रह रहे डॉक्टर से मरीज की बात करायी जाती है और मर्ज के अनुसार दवा प्रेसक्राइब किया जाता है।

ग्रामीण डिजिटल क्लीनिक में तैनात स्वास्थ्य कर्मी मरीज को प्रेसक्रिप्शन के अनुसार दवाईयां दे देते हैं। इस तरह मेडिशाला डिजिटल क्लीनिक की सेवा लेने वाले मरीज शहर में आने और लम्बी लाईन लगा कर डॉक्टर की कन्सलटेन्सी लेने की दुश्वारियों से बच जाते हैं।

मेडिशाला की टेलीमेडिसीन क्लीनिक में अब तक डेढ़ लाख से अधिक मरीजों का ईलाज किया जा चुका है। देश भर के करीब साढ़े तीन सौ डॉक्टर मेडिशाला के माध्यम से ग्रामीण मरीजों को अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार स्टार्ट-अप नीति के तहत मेडिशाला हेल्थकेयर प्रा0 लि0 को स्टार्ट-अप के रूप में मान्यता दी गई है। इस नीति के तहत उन्हें 10 लाख रूपये की सहायता प्राप्त हुई है।

कम्पनी ने मार्केट से भी करीब 20 लाख रूपयों की व्यवस्था की है। चारो पार्टनरों ने कम्पनी के काम को आपस में विभाजित कर लिया है। समस्तीपुर के नरहन एस्टेट निर्बाधित कम्पनी में मो0 अमानुल्लाह तकनीकी पक्ष देखते हैं तो रितुराज ऑपरेशन से जुड़े हुए कामों को। ग्रामीण क्षेत्रों में कम्पनी के संबंध में जागरूकता फैलाने का काम सुमन सौरव ने अपनी कंधों पर ले रखा है। जबकि प्रिंस कुमार वित्त और मार्केटिंग का काम देखते हैं।

कम्पनी में अभी 18 लोग काम कर रहे हैं। कम्पनी के तीन टेलीमेडिसीन सेन्टर स्थापित किये जा चुके हैं जबकि 17 दवा दुकानों के साथ कम्पनी की साझेदारी हो चुकी है। स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए मेडिशाला द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जाता है। साथ ही यूट्यूब, फेसबुक, टवीट्र और इन्स्टाग्राम पर अच्छे स्वास्थ्य के संबंध में वीडियो बनाकर कर कम्पनी द्वारा लोड किया जाता है। ◉

बिहार एमएसएमई कनेक्ट-2023

सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई के उद्यमियों के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला

उद्योग विभाग के तत्वावधान में पटना के ज्ञान भवन में बिहार एमएसएमई कनेक्ट 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अमीर सुबहानी, भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव बी बी स्वैन तथा उद्योग विभाग बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने किया। कार्यक्रम में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी विनीत कुमार, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक शिव ओम दीक्षित, उद्योग निदेशक पंकज दीक्षित तथा सभी प्रमुख बैंकों के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि बिहार में लघु एवं मध्यम उद्योग सेक्टर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार की अनेक योजनाएं हैं जिनका विशेष महत्व है। लघु एवं मध्यम उद्यमों से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं में विश्वसनीय होती हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बैंकों ने पीएमईजीपी और पीएम एफएफएमई कार्यक्रमों को लागू करने में अच्छा सहयोग दिया। बिहार के समग्र विकास के लिए एमएसएमई मंत्रालय से हमें अधिक फंड और अधिक योजनाओं की आवश्यकता है।सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव बी बी स्वैन ने कहा कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान लगभग 30% है भारत के कुल निर्यात में लगभग 45% योगदान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का है। कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र ही है। हमारी योजना है कि अगले 10 वर्षों में इस सेक्टर में करीब 30 करोड़ लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं।

उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने कहा कि एमएसएमई उद्यमियों के लिए कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य छोटे उद्योग से प्रारंभ करने वाले उद्यमियों की हौसला अफजाई करना है। सरकार और बैंकों से प्राप्त सुविधाओं का उपयोग करके सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयां तेजी से आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 10 लाख रुपया तक की सहायता पाने वाली कुछ औद्योगिक इकाइयों का कारोबार अब करोड़ों में भी पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत करीब 29000 लोगों को उन्नीस सौ करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में योजना के तहत उद्यमियों को 1500 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क्रियान्वयन में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बैंकों और उनकी

शाखाओं को पुरस्कृत किया गया।

भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक शिव ओम दीक्षित, पंजाब नेशनल बैंक के जोनल हेड पीसी बेहरा, बैंक ऑफ इंडिया की महाप्रबंधक

पुष्पा चौधरी, केनरा बैंक के सर्किल हेड श्रीकांत एम भांदीवाद, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डीजीएम अजय बंसल, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के चेयरमैन सोहेल अहमद, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा और यूको बैंक के धीरज पटवर्धन ने मुख्य सचिव, बिहार सरकार और भारत सरकार के एमएसएमई सचिव से पुरस्कार ग्रहण किया। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक की मधुबनी और औरंगाबाद शाखा, पंजाब नेशनल बैंक के नारदीगंज और नया भोजपुर शाखा, बैंक ऑफ इंडिया के इस्लामिया कॉलेज लक्ष्मीपुर शाखा तथा कटिहार शाखा, केनरा बैंक के बुद्ध मार्ग शाखा और बिहटा शाखा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नवादा शाखा और वारसलीगंज शाखा, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के मधुबनी शाखा और मलमलिया मोड़, पश्चिम चंपारण शाखा, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के बिशनपुर, समस्तीपुर शाखा तथा बेन, बिहार शरीफ शाखा तथा यूको बैंक के नवादा शाखा और सोनो, जमुई शाखा को पीएमईजीपी कार्यक्रम के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पुरस्कृत किया गया। मौके पर पीएमईजीपी कार्यक्रम के 16 लाभुकों को स्वीकृत ऋण का चेक सौंपा गया।

इससे पहले उद्योग विभाग की ओर से तकनीकी विषयों पर तीन सत्रों में विशेष जानकारी दी गई। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के निदेशक डॉ राणा सिंह ने मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर उद्यमियों का मार्गदर्शन किया। उद्यमियों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। ◉

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत बेहतरीन कार्य निष्पादन के लिए पुरस्कृत किए गए बैंको का विवरण

क्र.	राज्य स्तर पर पुरस्कृत बैंक का नाम	संबंधित बैंक की कार्य निष्पादन की शाखाएँ	
1.	भारतीय स्टेट बैंक	मधुबनी मुख्य शाखा, जिला - मधुबनी	औरंगाबाद मुख्य शाखा, जिला - औरंगाबाद
2.	पंजाब नेशनल बैंक	नारदीगंज मुख्य शाखा, जिला - नवादा	नया भोजपुर मुख्य शाखा, जिला - बक्सर
3.	बैंक ऑफ इंडिया	इस्लामिया कॉलेज लक्ष्मीपुर मुख्य शाखा, जिला - सीवान	इस्लामिया कॉलेज लक्ष्मीपुर मुख्य शाखा, जिला - कटिहार
4.	केनरा बैंक	बुद्ध मार्ग मुख्य शाखा, जिला - पटना	बिहटा मुख्य शाखा, जिला - पटना
5.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	नवादा मुख्य शाखा, जिला - नवादा	वारसलीगंज मुख्य शाखा, जिला - नवादा
6.	उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक	मधुबनी मुख्य शाखा, जिला - प. चम्पारण	मलमलिया मोड मुख्य शाखा, जिला - प. चंपारण
7.	दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक	बिशनपुर मुख्य शाखा, जिला - समस्तीपुर	बेन मुख्य शाखा, जिला - बिहार शरीफ
8.	यूको बैंक	नवादा मुख्य शाखा, जिला - नवादा	सोनो मुख्य शाखा, जिला - जमुई

समाधान यात्रा और उद्योग की रफ्तार में तेजी

आंकड़ों के आईने में विकास की रफ्तार को देखने-समझने की कोशिश होती है। लेकिन बिहार के दूरदर्शी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास की जमीनी हकीकत देखने खुद निकल पड़े। समस्या समाधान के लिए राज्यभर में यात्रा की। मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा लगातार चर्चा में रही, क्योंकि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री समस्या समाधान के लिए कृत संकल्पित दिखे।

आंकड़ों के आईने में विकास की रफ्तार को देखने-समझने की कोशिश होती है। लेकिन बिहार के दूरदर्शी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास की जमीनी हकीकत देखने खुद निकल पड़े। समस्या समाधान के लिए राज्यभर में यात्रा की। मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा लगातार चर्चा में रही, क्योंकि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री समस्या समाधान के लिए कृत संकल्पित दिखे। विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए लगातार निर्देश देते रहे। बड़ी घोषणाएं करते रहे। समस्याओं का ऑन स्पॉट समाधान करते रहे। उद्योग-धंधों को बढ़ाने पर बल देते रहे।

सच कहिए, तो बिहार के विकास को लगातार गति मिल रही है। विकास के पथ पर बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। खासकर उद्योग-धंधों और आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। राज्य सरकार की योजनाएं किस रफ्तार में चल रही हैं, इसे देखने के लिए मुख्यमंत्री सभी 38 जिलों में समाधान यात्रा पर गये। चार जनवरी को पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई यह यात्रा 15 फरवरी को पूरी हुई। इस दौरान उद्योग-धंधों के विकास पर मुख्यमंत्री का खूब जोर रहा।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहारी युवाओं, महिलाओं, अनुसूचित जाति- जनजाति, अति पिछड़ों को उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। इसमें 5 लाख रुपए

का अनुदान होता है। शेष 5 लाख रुपए किस्तों में लौटाने होते हैं, जिस पर मात्र 1 प्रतिशत ब्याज देना है। इस योजना के लिए राज्य सरकार की ओर से जिलावार लक्ष्य निर्धारित है। इसके लिए सरकार ने 400 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। इसमें 200 करोड़ रुपए युवा उद्यमी और 200 करोड़ रुपए महिला उद्यमी के लिए स्वीकृत हैं। योजना के लाभ के लिए इच्छुक महिला और युवा को बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है। आवेदकों की उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। बिहार सरकार ने इस प्रक्रिया के लिए एक समिति का गठन किया है। यह 11 सदस्यीय समिति लाभार्थियों का चयन करती है।

योजना की स्थिति का जायजा लेने मुख्यमंत्री कई जगहों पर गए और जायजा लिया। समाधान यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भागलपुर में उद्यमी योजना के तहत सीपेट कैंपस में उद्योग विभाग द्वारा लगाई गई उत्पादित सामाग्रियों से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और जिले के कुल 81 लाभुकों को देय राशि से संबंधित चेक प्रदान किये। साथ ही लघु उद्यमियों को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

इसी तरह पीतल के बर्तनों के लिए देश भर में चर्चित बिहटा के परेब का जायजा लेने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने कुटीर उद्योग, जीविका एवं उद्योग विभाग के स्टॉल का जायजा लिया, फिर 9.60 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की घोषणा की। इस राशि से पीतल उद्योग के लिए अत्याधुनिक तकनीकों पर आधारित

मशीनों तथा कॉमन फैसिलिटी सेंटर की स्थापना की जाएगी।

सारण में नीतीश कुमार ने उद्यमी योजना के तहत स्थापित जूता फैक्ट्री का अवलोकन किया। यहां उन्होंने जीविकोपार्जन योजना के तहत 90 परिवारों को 12 लाख 23 हजार 950 रुपए का चेक सौंपा। समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पूर्णिया के सदर प्रखंड के मल्हनी गांव में उद्यमी योजना के तहत 66 लाभुकों के बीच ढाई करोड़ रुपए के चेक प्रदान किए।

गोपालगंज में भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों से मुखातिब हुए। यहां उन्होंने जीविका संपोषित स्वयं सहायता समूहों को 75.43 करोड़ और सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत 1165 परिवारों को 2. 60 करोड़ रुपये के चेक दिए।

नवादा में नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना आदि के संबंध में दिए गए लाभ के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। यहां उन्होंने सतत् जीविकोपार्जन योजना अंतर्गत 545 लाभान्वित परिवारों को 1.91 करोड़ रुपये के चेक दिए।

सुपौल में समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश कुमार मल्हनी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने विकास योजना का जायजा लिया। इस दौरान

उन्होंने उद्यमी योजना के तहत 66 लाभुकों के बीच ढाई करोड़ रुपए के चेक बांटे। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री गया भी पहुंचे। यहां नक्सलग्रस्त बांकेबाजार में हो रही लेमनग्रास की खेती का जायजा लिया और लेमनग्रास की खेती को बढ़ाने का निर्देश दिया, ताकि इस पर केंद्रित उद्योग-फैक्ट्री स्थापित हो सके। गया में जल्द ही लेमनग्रास से जुड़े साबुन, फिनाइल, परफ्यूम, चाय आदि की फैक्ट्री स्थापित होगी।

दूसरी तरफ बिहार से पलायन को रोकने के लिए भी मुख्यमंत्री कृत संकल्पित हैं। कोरोना काल में बिहारियों ने जो दुख-दर्द सहा, इसका एहसास सभी को है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार में ही अधिक से अधिक उद्योग-धंधे स्थापित हों, रोजगार के अवसर मिले, ताकि बिहारियों को रोजी-रोटी के लिए बाहर न जाना पड़े। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का मकसद छोटे कारोबारियों की मदद करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वे अपने साथ-साथ राज्य का भी विकास कर सकें।

बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत आवेदनों की प्रतीक्षा सूची जल्द ही तैयार हो जाएगी। इस सूची में करीब 65000 आवेदक होंगे। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 200-200 लाभार्थियों का चयन होगा। इसका मतलब है कि शेष आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत साल 2022 में विभाग को 12971 आवेदन प्राप्त हुए थे। अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के नागरिकों के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग से योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत 16327 आवेदन प्राप्त हुए थे। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत सभी चार योजनाओं के लिए सरकार द्वारा 200-200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और करीब आठ से 10 हजार नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। कुल मिलाकर बिहार के विकास को गति देने की महती कोशिश जारी है। मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा से इसकी रफ्तार में और तेजी आयी है।

:: दीपक दक्ष ◉

बिहार कनेक्ट-23
स्टार्ट-अप इकाइयों को मिला निवेशकों से संवाद का सीधा अवसर

स्टार्ट-अप उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। बिहार स्टार्ट-अप नीति के तहत अब तक 327 स्टार्ट-अप को प्रमाणिकृत किया जा चुका है और उन्हें 16.83 करोड़ रूपये की राशि सीड फंड के रूप में दी जा चुकी है।

स्टार्ट-अप उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। बिहार स्टार्ट-अप नीति के तहत अब तक 327 स्टार्ट-अप को प्रमाणिकृत किया जा चुका है और उन्हें 16.83 करोड़ रूपये की राशि सीड फंड के रूप में दी जा चुकी है। लेकिन मात्र सीड फंड से स्टार्ट-अप इकाइयों का पूर्ण विस्तार संभव नहीं है। उन्हें अपने विस्तार के लिए मार्केट से पूंजी प्राप्त करना जरूरी है। बिहार स्टार्ट-अप नीति के तहत एन्जेल ग्रुप्स और कैटेगरी-1 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेन्ट फंड द्वारा स्टार्ट-अप में निवेश की राशि के बराबर अधिकत 50 लाख रूपये तक का मैचिंग लोन बिहार स्टार्ट-अप फंड से दिये जाने का प्रावधान है। स्टार्ट-अप इकाइयों को एन्जेल ग्रुप्स और इन्वेस्टमेन्ट फंड मैनेजरों से सपोर्ट दिलाने के उद्देश्य से 15 और 16 मार्च 2023 को पटना के मौर्यालोक स्थित बी-हब तथा ज्ञान भवन में बिहार कनेक्ट-23 इन्वेस्टर्स सम्मिट फॉर स्टार्ट-अप इन बिहार का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राष्ट्रीय स्तर के 16 कम्पनियों के फंड मैनेजरों ने हिस्सा लिया और बिहार के स्टार्ट-अप उद्यमियों का मार्गदर्शन किया। पूरे आयोजन में 123 उद्यमियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 45 को पिच सेसन के लिए चयनित किया गया। पिच सेसन के पहले ग्रुप में 15 स्टार्ट-अप उद्यमियों को और दूसरे ग्रुप में 30 स्टार्ट-अप उद्यमियों को अपना पक्ष विशेषज्ञ पैनल के समक्ष रखने का मौका मिला। इनमें 23 स्टार्ट-अप कम्पनियों को निवेशकों और वेंचर इकाइयों द्वारा अगले दौर के लिए चयनित किया गया। ज्ञान भवन में आयोजित समापन समारोह में स्टार्ट-अप उद्यमियों को संबोधित करते हुए बिहार के उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि सभी अपने स्टार्ट अप और नए आइडियाज के माध्यम से न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के भविष्य को संवार रहे है।

बिहार औद्योगीकरण के नए युग की ओर तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में निवेश की अपार संभावनाएं है। बिहार के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने तथा निवेशकों के विश्वास को जीतने के लिए हमलोग पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ काम कर रहें हैं। बिहार के औद्योगिकीकरण के संकल्प को पूरा करने के लिए हमने कई लक्ष्यों का निर्धारण किया है- जैसे स्टार्ट-अप और इनोवेशन को बढ़ावा देना, बड़े उद्योगों की स्थापना, एम0एस0एम0ई0 को व्यापक प्रसार देना, बिहार के पारंपरिक उद्योग जैसे-हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खादी, ग्रामोद्योग को मजबूती प्रदान करना।

बिहार में स्टार्टअप्स के ग्रोथ के लिए शानदार ईको सिस्टम तैयार हो रहा है जिसमें स्टार्ट-अप को-ट्रेनिंग, वित्तीय सहायता, को-वर्किंग-सह- को-लर्निंग स्पेस, मार्केटिंग, तकनीकी विकास जैसे सहयोग मिल रहे हैं, ताकि न सिर्फ स्टार्ट-अप उद्यमियों की सफलता सुनिश्चित हो बल्कि देश और दुनिया के बड़े स्टार्ट अप्स की कतार में बिहार के स्टार्ट अप्स भी खड़े हो सकें।

बिहार में स्टार्ट-अप को नई ऊर्जा और गति प्रदान करने के लिए 2017 के बाद नये प्रावधानों के साथ बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2022 लागू की गई ताकि स्टार्ट-अप को सरल और त्वरित गति से सहायता दी जा

सके।

स्टार्ट अप और नवाचार को बढ़ावा देना आर्थिक विकास और मजबूती के लिए आवश्यक है। बिहार सबसे बेहतर इमर्जिंग स्टार्ट-अप इको सिस्टम वाला राज्य है। दुनिया में भारत स्टार्ट-अप इको सिस्टम तीसरे स्थान पर है।

उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौण्डरीक ने कहा कि बिहार में स्टार्ट-अप 32.70 करोड़ रुपये सीड फंड के रूप में स्वीकृत किये जा चुके हैं। अब तक 327 स्टार्ट-अप रजिस्टर्ड हो चुके हैं और इन्हें 16 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बिहार में 50 से अधिक स्टाट-अप को महिलाएँ लीड कर रही हैं जो विशेष बात है। स्टार्ट-अप उद्यमियों की मदद के लिए उद्योग विभाग ने इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना तथा चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, पटना के साथ टाईअप किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में उद्यमिता और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हमें अपना इको सिस्टम मजबूत करना है। बिहार के

कार्यक्रम में चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के डॉ० राणा सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमोद कुमार सहित स्टार्ट-अप कम्पनियों के लगभग 200 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

प्रतिभागी निवेशक	कम्पनी
डॉ. कैलाश पिन्जानी	वेन्कैप्ट बिजनेस वेन्चर्स
सुश्री प्ररेणा सांगोई	100 x VC
सुश्री आयुषी कृष्ण कुमार शाह	आई.टी.आई. ग्रोथ ऑपरचुनिटी फंड
श्री आर्यमन राधेश कागजी	एम.जी.ए. वेन्चर्स
श्री कुमार सौरव	वेन्चर कैटालिस्ट
श्री कौशिक शेखर	इन्लाईटेन वीसी.ऑनलाईन
सुश्री स्नेहाली मानसिंह खामकर	इन्लाईटेन वीसी.ऑनलाईन
श्री संनत मंडल	इंडिया एन्जेल नेटवर्क
श्री मनीष श्रीवास्तव	अल्फा वैल्यू कन्सलटिंग
श्री आदित्य पांडे	एक्सीलोर
श्री अनिरूद्ध जयगोपाल	ब्रिज रीप
श्री विनीत भसीन	ट्रांजीसन वेन्चर कैपिटल
श्री जसभारत राणावत	लीड एन्जेल्स
श्री मिलिन्द पाठक/श्री राहुल पांडे	रूट मोबाइल
डॉ. अरविन्द झा	मिथिला एन्जेल नेटवर्क

स्टार्ट-अप कृषि और हैण्डलूम हस्तकरघा के साथ-साथ रोबोटिक्स और ड्रोन बनाने के काम में भी लगे हुए हैं। भविष्य में ये स्टार्ट-अप पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाएँगे। बिहार कनेक्ट 2023 का संयोजन उद्योग निदेशक पंकज दीक्षित ने किया। ◉

गणतंत्र दिवस पर उद्योग विभाग की झांकी

गांधी मैदान में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में उद्योग विभाग ने उत्साह के साथ भाग लिया। गणतंत्र दिवस परेड में उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की ओर से प्रस्तुत झांकी में बिहार के औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों पर प्रकाश डाला गया। बिहार राज्य टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी, बिहार स्टार्टअप नीति और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से रोजगार सृजन के प्रयासों को प्रमुखता से दिखाया गया। उद्योग विभाग की झांकी को काफी सराहना मिली।

राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस
बिहार में खड़े होंगे वर्ल्ड क्लास स्टार्ट-अप

बेहतर है बिहार का स्टार्टअप इकोसिस्टम

उद्योग विभाग द्वारा मौर्यलोक स्थित स्टार्टअप सेंटर बी हब में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्टार्टअप उद्यमियों को संबोधित करते हुए बिहार के विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम बेहतर बनाने के लिए उद्योग विभाग काम कर रहा है। बिहार में भी वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप तैयार होने की पूरी संभावना है। स्टार्टअप इकाइयों को उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ाने और सतत प्रयत्नशील रहने के लिए कठिन मेहनत की जरूरत है। उन्होंने कहा कि काम के प्रति पूर्ण समर्पण, लगन और काम को अंजाम तक ले जाने की भावना ही स्टार्टअप को सफल बनाएगी।

विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह ने कहा कि डिग्री प्राप्त कर लेना आसान है। लेकिन सपनों को जीने के लिए दिन-रात को एक कर देना होता है। स्टार्टअप उद्यमियों को न सिर्फ अपने सपने साकार करने हैं बल्कि अपने निवेशकों के सपनों को भी साकार करना है। इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन करके विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंह, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौण्डरीक, सिडबी की महाप्रबंधक अनुभा प्रकाश, उद्योग निदेशक पंकज दीक्षित और चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना के निदेशक डॉ राणा सिंह ने किया।

कार्यक्रम में सभी उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की बधाई देते हुए उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौण्डरीक ने कहा कि स्टार्टअप के लिए पैशन, कमिटमेंट और अनलिमिटेड एनर्जी की आवश्यकता है। इनकी बदौलत ही स्टार्टअप को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। स्टार्टअप उद्यमी सही प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ काम करते हुए अपनी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले जाएं जिससे बिहार का नाम रोशन हो। कार्यक्रम में सिडबी की महाप्रबंधक अनुभा प्रकाश ने कहा कि स्टार्टअप की सफलता के लिए बेहतरीन को सिस्टम का होना आवश्यक है। बी-हब एक ऐसा ही मंच है जहां बिहार के सभी स्टार्टअप एक साथ मिल बैठकर के एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप के तहत सिर्फ सीडफंड प्राप्त करना मकसद नहीं होना चाहिए बल्कि एंजल इन्वेस्टर्स के माध्यम से बड़ा निवेश हेतु प्रयत्नशील रहना चाहिए।

बिहार में भी वर्ल्ड क्लास स्टार्टअप तैयार होने की पूरी संभावना है। स्टार्टअप इकाइयों को उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ाने और सतत प्रयत्नशील रहने के लिए कठिन मेहनत की जरूरत है।

कार्यक्रम में सभी अतिथियों का स्वागत चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के निदेशक डॉ राणा सिंह ने किया। उद्योग निदेशक पंकज दीक्षित ने धन्यवाद ज्ञापन किया। स्टार्टअप दिवस पर स्टार्टअप कंपनी देहात के को-फाउंडर शशांक, ग्राम श्री किसान की आस्था सिंह, हस्तसंस्कृति प्रा. लि. की ममता और एग्रिक्स एग्रोटेक के डॉ निलय पाण्डेय ने भी अपने विचार साझा किए। ◉

नई दिल्ली में आयोजित हुआ बिहार इन्वेस्टर कनेक्ट

बिहार में निवेश के लिए
खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को निमंत्रण

21 मार्च, 2023 को उद्योग विभाग द्वारा नई दिल्ली में बिहार इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश के अवसरों के बारे में संभावित निवेशकों को विस्तार से जानकारी दी गई।

21 मार्च, 2023 को उद्योग विभाग द्वारा नई दिल्ली में बिहार इन्वेस्टर कनेक्ट का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश के अवसरों के बारे में संभावित निवेशकों को विस्तार से जानकारी दी गई। इस इन्वेस्टर मीट में बिहार के विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक, नई दिल्ली में बिहार के स्थानिक आयुक्त श्री कुन्दन कुमार, उद्योग निदेशक श्री पंकज दीक्षित और खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के निदेशक श्री विवेक रंजन मैत्रेय ने निवेशकों को बिहार में निवेश करने के फायदों के बारे में बताया। विकास आयुक्त श्री विवेक कुमार सिंह ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए आवश्यक 5-P पॉलिसी, पोटेन्शियल, पॉपुलेशन, पानी और पर्सनेल बिहार में मौजूद है। इसलिए बिहार में खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में निवेश फायदे का सौदा होगा। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री संदीप पौण्डरीक ने बताया कि बिहार का उपभोग पैटर्न तेजी से बदल रहा है। फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए भारी मात्रा में कच्ची सामग्री, पानी और श्रम संसाधन बिहार में मौजूद हैं जो बिहार के निवेश के लिए आकर्षक डेस्टिनेशन बनाता है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों में पर्याप्त जमीन उपलब्ध होने के साथ-साथ बिहार में प्लग एण्ड प्ले सुविधाओं के साथ औद्योगिक शेड भी कम किराये पर उपलब्ध है। इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की सचिव श्रीमती अनिता प्रवीण ने भी अपने विचार रखें।

निवेशकों की ओर से ब्रिटानिया कम्पनी के श्रीकांत ने बताया बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग चालू करने के लिए कम कीमत पर जमीन और सरकारी सुविधाएँ उपलब्ध है। कोका कोला कम्पनी के श्री मोहन ने बिहार में उद्योग लगाते समय सरकार की ओर से मिली सुविधाओं और सहायता का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी कम्पनी बिहार में एक और बॉटलिंग प्लांट लगाने का इरादा रखती है। अदानी विलमर ने राज्य में 800 करोड़ रूपये के निवेश की योजना पर काम करने की जानकारी दी। इन्वेस्टर सम्मिट में 60 से अधिक कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ◉

प्रधानमंत्री गति शक्ति
नेशनल मास्टर प्लान

राष्ट्रीय स्तर पर आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु गति शक्ति योजना बनायी गयी है, जिसके तहत 100 लाख करोड़ रू0 के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके अन्तर्गत अलग-अलग मंत्रलयों के अन्तर्गत चल रहे सभी योजनाओं को एकीकृत करते हुए एक नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल को आरम्भ किया गया है।

राष्ट्रीय स्तर पर आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु गति शक्ति योजना बनायी गयी है, जिसके तहत 100 लाख करोड़ रू0 के बजट का प्रावधान किया गया है। इसके अन्तर्गत अलग-अलग मंत्रलयों के अन्तर्गत चल रहे सभी योजनाओं को एकीकृत करते हुए एक नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल को आरम्भ किया गया है। इस पोर्टल पर सभी विभागों के द्वारा आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु किये जा रहे कार्यों को दूसरे विभाग द्वारा भी देखा जा सकता है एवं सभी विभागों के आपसी समन्वय से देश की विकास योजनाओं को ससमय कम लागत में एवं अधिक प्रभावकारी ढंग से लागू किया जा सकेगा। भारत सरकार की यह एक महत्वकांक्षी योजना है। इसके द्वारा देश में भारी संख्या में रोजगार सृजन की संभावना है। सभी विभागों द्वारा आधारभूत संरचनाओं के लिए किये जा रहे कार्यों के आंकलन के अनुसार इसके माध्यम से लाखों रोजगार सृजन की संभावनाएँ है।

गतिशक्ति योजना के अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा निम्नलिखित योजनाओं का संचालन राज्य सरकारों के सहयोग से किया जा रहा है। राज्य सरकारों की भी इन सभी योजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने की बड़ी जिम्मेवारी है क्योंकि इसके बगैर सरकार की कोई योजना धरातल पर नहीं आ पायेगी । इसके अन्तर्गत भारत माला परियोजना (राष्ट्रीय राज्य मार्गों का नेटवर्क विस्तार) , सागरमाला, इनलैण्ड वाटरवे , ड्राई पोर्ट उड़ान इसके अतिरिक्त इकनॉमिक जोन के अन्तर्गत टेक्सटाईल कलस्टर , फार्मास्यूटिकल कलस्टर, डिफेंसकोरिडोर, इकोनौमिक पार्क, इन्डस्ट्रीयल कोरिडोर फिसिंग कलस्टर, एग्री जोन इत्यादि इस विस्तृत कार्य योजना से पूरे देश में कनेक्टिविटी में गति आयेगी, व्यापार के नये आयाम सृजित होगा, व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और सबसे सुखद बात होगी कि उत्पादन लागत कम होगी जिससे वस्तुओं की कीमत भी कम होगी।

इस योजना की सफलता हेतु व्यापक रूप से ISRO के माध्यम से प्राद्योगिकी का लाभ उठाने की योजना भी BISAG-N के माध्यम से विकसित की गई है। (Bhasakarachrya National Institute for Space Application and Geoinformatics) BISAG-N के माध्यम से पूरे देश की सभी योजनाओं जो चालू है या जिसके किये जाने की कार्य योजना बनाई गयी है उन्हें नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल पर देखा जा सकता है। जिससे सभी विभाग अपनी कार्य योजनाओं को बनाते समय दूसरे विभाग की योजना को देखते हुए अपनी योजनाओं को तैयार कर सकेगें। भारत सरकार के वित्त मंत्री द्वारा 2022-23 के बजट में पी0एम0 गति शक्ति परियोजना के सन्दर्भ में कई बड़ी घोषणाएँ की गई है।

इन सभी परियोजनाओं की कुललागत 107 लाख करोड़ की है जिससे देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर को नया स्वरूप देने की योजना है। इसके अन्तर्गत रेल, सड़क, सहित कुल 16 विभागों का BISAG-N द्वारा निर्मित नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल पर लाया गया है जिससे सभी विभाग आपसी समन्वय से आने वाली रूकावटों को ससमय दूर कर सकेगे। वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण के दरम्यान बताया गया कि इस योजनान्तर्गत 400 नई बन्दे भारत ट्रेन चलायी जायेगी एवं 100 पी0एम0 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल तैयार किया जायेगा।

लॉजिस्टिक की आवागमन हेतु नेशनल हाईवे के नेटवर्क को लगभग 25000 हजार किलोमीटर बढ़ाया जायेगा। 2022-23 में हीं 8 नये रोपवे को आर्डर किया जायेगा। इस पूरे योजना से सप्लाई चेन के नेटवर्क को सुदृढ़ किया जायेगा। गति शक्ति योजना में 11 औद्योगिक कोरिडोर 2 डिफेन्स कोरिडोर, 200 एयरपोर्ट हैलिपैड और वाटर एयरोड्राम एवं कुल 2 लाख किलोमीटर एन0एच0 नेटवर्क, सभी गॉवों में 4G कनेक्टिविटी 17000 कि0मी0 गैस पाईप लाईन और 200 से ज्यादा फिसिंग कलस्टर बनाने की योजना भी 2025 तक है।

यह स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार की इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए यह एक क्रांतिकारी कदम है। इससे देश के आर्थिक विकास को पूरजोर गति मिलेगी परन्तु इसमें सबसे ज्यादा केन्द्र एवं राज्यों के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता है एवं इससे भी ज्यादा जरूरी इसमें सभी भागिदारों चाहे वे सरकारी कर्मचारी/पदाधिकारी हो या निजी क्षेत्र के साझेदार हो उनकी महत्वकांक्षा कागजों पर निर्मित योजनाओं को धरातल पर उतारना होनी चाहिए। इसके बगैर योजना का लाभ देश को नहीं मिल पायेगा।

:: रंजन कुमार सिन्हा

गुरुनानक नाम इन्टरप्राईजेज

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से मिली सहायता तो चल पड़ा कारोबार

नये उद्यमियों को संदेश देते हुए वह कहते हैं कि उद्योग चलाने के लिए पूंजी का होना आवश्यक है, लेकिन व्यवहकार कुशलता और कड़ी मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। अभी उनके द्वारा उत्पादित पुस्तिका का वितरण बेगूसराय जिला में हो रहा है। वह अपनी यूनिट का विस्तार करते हुए दूसरे कई जिलों में भी अपनी कम्पनी का नोट-बुक बेचना चाहते हैं।

कठिन परिस्थितियों से घबराये बिना जो लोग लगातार प्रयास करते हैं वे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चले जाते हैं। बेगूसराय जिला के बलिया प्रखण्ड निवासी विवेक कुमार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से सहायता मिलने के बाद पूरी शिद्दत के साथ उद्यमिता की राह पकड़ी। सरकारी विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा लेने वाले विवेक कुमार ने उच्चतर माध्यमिक की पढ़ाई बेगूसराय में रहकर पूरी की। निजी संस्थाओं में बड़े पद पर नियुक्ति के लिए उनके पास किसी प्रकार की प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी। ऐसे में बेरोजगारी की समस्या सामने दिख रही थी।

जिला उद्योग केन्द्र, बेगूसराय जाने पर उन्हें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने योजना के तहत मिलने वाले 10 लाख रूपये की सहायता के लिए आवेदन भरा। विभाग से उनका चयन हो गया जिसके बाद उन्होंने प्रबंधकीय प्रशिक्षण लिया और नोट-बुक बनाने का कारोबार चालू किया। लगन, मेहनत और सद्व्यवहार की अतिरिक्त पूंजी का उपयोग करते हुए विवेक कुमार ने कई विद्यालय के प्रबंधकों से समन्वय किया और भारी मात्रा में नोट-बुक की आपूर्ति का क्रयादेश प्राप्त किया। इस तरह उनका कारोबार विस्तृत होने लगा। पिछले साल उनके उद्यम ने 20 लाख से अधिक का कारोबार किया। विवेक कुमार कहते हैं कि हम सभी जीवन में सफलता चाहते हैं, लेकिन कामयाबी की राह आसान नहीं होती।

सफलता उसी को मिलती है जो कड़ी मेहनत करता है। उन्होंने कहा कि उद्योग विभाग से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उन्हें जो अनुदान और ऋण प्राप्त हुआ है उसके लिए वह उद्योग विभाग के आभारी हैं। उद्योग की स्थापना से ही उनकी जीवन शैली में सुधार आया है और पूरे परिवार का भरण-पोषण करने में आसानी हुई है।

नये उद्यमियों को संदेश देते हुए वह कहते हैं कि उद्योग चलाने के लिए पूंजी का होना आवश्यक है, लेकिन व्यवहकार कुशलता और कड़ी मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। अभी उनके द्वारा उत्पादित पुस्तिका का वितरण बेगूसराय जिला में हो रहा है। वह अपनी यूनिट का विस्तार करते हुए दूसरे कई जिलों में भी अपनी कम्पनी का नोट-बुक बेचना चाहते हैं। ◉

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना

बढ़ते उद्यमी, बढ़ता कारोबार

ऊँची उड़ान के लिए बिहार है तैयार

लाभुकों की संख्या 29,828

सहायता राशि (करोड़ रू. में) 1910

पद्मश्री कपिल देव प्रसाद

बावनबूटी कला से मिली ख्याति

बिहार के नालंदा जिला के बिहारशरीफ प्रखंड के बसवन बिगहा के बुनकरों की पहचान देश-दुनिया में है। यहां निर्मित बावनबूटी साड़ी, चादर और पर्दे की मांग देश-दुनिया में है। बुनकर कपिलदेव प्रसाद ने इसमें चार चांद लगाया है।

बिहार के नालंदा जिला के बिहारशरीफ प्रखंड के बसवन बिगहा के बुनकरों की पहचान देश-दुनिया में है। यहां निर्मित बावनबूटी साड़ी, चादर और पर्दे की मांग देश-दुनिया में है। बुनकर कपिलदेव प्रसाद ने इसमें चार चांद लगाया है। कपिल देव प्रसाद 15 वर्ष की आयु से ही बुनकर उद्योग से जुड़े है और करीब 55 सालों से बुनकर का काम करते आ रहे हैं। अब भी खुद बुनकरी का काम करते हैं। साथ ही लोगों को भी बुनकरी का काम सिखाते हैं। उन्होंने अपनी तपस्या से बावनबूटी कला को बढ़ावा दिया। इसके लिए वर्ष 2023 में कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए कपिल देव प्रसाद को पद्मश्री से सम्मानित किया गया।

कपिलदेव प्रसाद बताते हैं कि बिहार शरीफ स्थित नवरत्न महल में सरकारी बुनकर स्कूल खुला था। यह स्कूल हाफ टाइम था, जहां नियमित पढ़ाई जारी रखते हुए बच्चे बुनकरी सीखते थे। 1990 में स्कूल बंद हो गया तो बसवन बिगहा प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति का गठन किया गया। यह समिति बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़कर लोग इसका ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। बिहार राज्य निर्यात निगम की मदद से उनके गांव में शेड बनाया गया। इसके बाद बावन बूटी कला को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ले जाने में मदद मिली। हथकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग एवं बिहार राज्य हैंडलूम एवं हथकरघा निगम से भी उन्हें भरपूर सहयोग मिला।

खास तरह के एक जैसे 52 टांकों की कला

कपिल देव प्रसाद की पहचान इसलिए भी है, क्योंकि उन्होंने बाप-दादा से सीखे हुनर को लोगों में बांटकर रोजगार का एक माध्यम विकसित कर दिया। बावनबूटी मूलतः एक तरह की बुनकर कला है। सूती या तसर के कपड़े पर हाथ से एक जैसी 52 बूटियां यानी मौटिफ टांके जाने के कारण इसे बावनबूटी कहा जाता है। बूटियों में बौद्ध धर्म-संस्कृति के प्रतीक चिह्नों की बहुत बारीक कारीगरी होती है। बावनबूटी में कमल का फूल, बोधि वृक्ष, बैल, त्रिशूल, सुनहरी मछली, धर्म का पहिया, खजाना, फूलदान, पारसोल और शंख जैसे प्रतीक चिह्न ज्यादा मिलते हैं। बावनबूटी की साड़ियां सबसे ज्यादा डिमांड में रहती हैं, वैसे इस कला से पूर्व परिचित लोग बावनबूटी चादर और पर्दे भी खोजते हैं। कपिल देव प्रसाद के दादा शनिचर तांती ने इसकी शुरुआत की थी। फिर पिता हरि तांती ने सिलसिले को आगे बढ़ाया।

महात्मा बुद्ध के काल से प्रसिद्ध है बावनबूटी कला

पद्मश्री कपिल देव प्रसाद ने बताया कि बावनबूटी कला में हर डिजाइन पर 52 बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी डिजाइनिंग चादर, तौलिया, गमछा, साड़ी और दूसरे किसी भी वस्त्र पर की जा सकती है। कपिल देव प्रसाद ने कहा कि बावनबूटी अति प्राचीन हस्तकला है और इसे बौद्ध परंपरा में भी स्थान मिला हुआ है। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित प्रतीक चिह्नों को बावनबूटी कला के माध्यम से प्रकट किया जाता है। कलाकार पीपल का पत्ता, कमल के फूल, बोधि वृक्ष, त्रिशूल, मछली, धम्मचक्र, फूलदान, शंख को कपड़े पर 52 बूटियों के माध्यम से प्रकट करते हैं। इस कला के माध्यम से वह भगवान बुद्ध को सम्मान देते हैं और उनकी महानता का बखान करते हैं।

बावनबूटी कला के मुरीद थे राजेंद्र बाबू

बावनबूटी कलाकार कपिल देव प्रसाद ने कहा कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद इस कला के मुरीद थे। जब वह देश के राष्ट्रपति थे तो राष्ट्रपति भवन के पर्दे बिहार के बसवन बीघा से जाते थे जिन पर बावनबूटी कलाकृतियां उकृत होती थी।

बावनबूटी कला में मिल सकता है लाखों लोगों को रोजगार

कपिल देव प्रसाद ने कहा कि इस कला में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं और लाखों लोग रोजगार पा सकते हैं। सरकार बावनबूटी कला को प्रोत्साहित कर रही है। बावनबूटी कला के कलाकारों को बाजार मिलेगा तो उनकी कला और निखरेगी। बावनबूटी कला वाली चादरें जर्मनी, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका में भी निर्यात की जाती हैं।

:: मनीष कुमार

पद्मश्री सुभद्रा देवी

पेपरमेशी कला से मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान

बिहार की शान हैं पद्मश्री सुभद्रा देवी। पेपरमेशी कला को घर की दीवारों से निकाल कर अंतरराष्ट्रीय पटल पर लेकर आने में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उद्योग विभाग के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना से जुड़कर उन्होंने यह कर दिखाया है। सुभद्रा देवी पेपरमेसी के क्षेत्र की सिद्धहस्त कलाकार हैं। उन्होंने बचपन में ही अपने घर में पेपरमेसी का काम होते देखा। इसके बाद वो इससे गुड़िया और खिलौना बनाने लगीं। यहीं से उन्होंने इस कला को सीखा और इसे लोगों तक पहुंचाया। मधुबनी की सुभद्रा देवी को वर्ष 2023 में कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया। पेपरमेशी मूल रूप से जम्मू-कश्मीर की कला के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन सुभद्रा देवी बचपन में इस कला से खेला करती थीं।

स्पेन जाकर लोगों को दे चुकी हैं प्रशिक्षण

सुभद्रा देवी दरभंगा के मनीगाछी से ब्याह कर मधुबनी के सलेमपुर पहुंचीं तो भी इस कला से खेलना नहीं छोड़ा। बचपन से इस कला में रुचि रखने के कारण इस क्षेत्र में आगे बढ़ती चली गईं। उन्होंने 100 से भी अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया है। स्पेन के लोगों को पेपरमेशी कला का प्रशिक्षण देने के लिए सुभद्रा देवी को भारत सरकार ने 2014 में 15 दिनों के लिए स्पेन भेजा था।

पेपरमेशी कला को दिया नया आयाम

एक समय की बात है जब मिथिला कला की खूब चर्चा होती थी, तब पेपरमेशी का जिक्र नहीं के बराबर होता था। इसका बाजार भी विकसित नहीं हो पाया था। ऐसे समय में प्रतिष्ठित कलाकार सुभद्रा देवी ने कला को नया आयाम दिया। सुभद्रा देवी कहती हैं कि उन्होंने अपनी कला यात्रा की शुरुआत मिथिला चित्रकला से ही की थी। उनकी कला में मिथिला की संस्कृति और परंपरा की झलक दिखाई देती है।

मिथिला पेंटिंग को मैंने नहीं छोड़ा : सुभद्रा

सुभद्रा देवी कहती हैं कि 70 के दशक में पटना में शिल्प अनुसंधान संस्थान के लिए मैंने कनिया-पुतरा (कपड़े), पेंटिंग (कागज) और सामा-चकेवा (मिट्टी) बनाया था। सामा-चकेवा को काफी पसंद किया गया और मुझे पुरस्कार मिला था। 90 के दशक में एक बार मद्रास गई तब उनको एक मैडम ने कहा कि 'राजा-रानी की शादी का सीन बना दीजिए'। इस पर उन्होंने कहा कि 'राजा-रानी की शादी का मुझे नहीं पता। रामचंद्र भगवान की शादी हुई न, वही विधि से शादी-विवाह को हम जानते हैं। कोहबर, कन्यादान, मंडप आदि पेपरमेशी पर बीस दिनों तक उन्होंने वहां बनाई थी। वे जोड़ देकर कहती हैं कि मिथिला पेंटिंग को मैंने नहीं छोड़ा।

यह है पेपरमेसी कला

पेपरमेशी (पापिए माशे) फ्रेंच शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है मसला हुआ या कटा हुआ कागज। इस कला में कागज को पहले पानी में भिगोया जाता है, फिर लुगदी बनाई जाती है। गोंद व फेविकोल के सहारे उसे एक आकार दिया जाता है। धूप में सुखाने के बाद उन पर विभिन्न रंगों से चित्रकारी की जाती है। सांचों (मोल्ड) का इस्तेमाल इस कला में होता रहा है पर सुभद्रा देवी अपने कुशल हाथों से ही इस कला को दशकों से गढ़ती रही। चर्चित मिथिला कलाकार चंद्रकला देवी भी पेपरमेशी कला से जुड़ी रहीं पर सही मायनों में सुभद्रा देवी ने इसे ऊंचाई पर पहुंचाया है।

पेपरमेशी कला का इतिहास

मुगल काल में पेपरमेशी कला का विकास हुआ। इस कला को लोग कश्मीर से जोर कर देखते रहे हैं। वहां पर इसकी विकसित परंपरा रही है। वर्ष 2019 में कश्मीर के फैयाज अहमद जान को पेपरमेशी के लिए पद्मश्री मिल चुका है। ऐसा नहीं है कि देश के अन्य भागों में इस कला का विकास नहीं हुआ हो। ओडिशा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश में भी इस कला के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। इस कला में ज्यादातर दैनंदिनी जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं, मुखौटे, खिलौने, टेबल लैंप, पेन स्टैंड, तश्तरी आदि दिखाई देते हैं। मिथिला में जो पेपरमेसी का रूप है वह अभी भी पारंपरिक लोक कथाओं और संस्कृति को समेटे है।

:: मनीष कुमार

बिहार क्राफ्ट फेयर

बिहार क्राफ्ट फेयर में लोगों ने जमकर उत्पादों की खरीदारी की और अपने घर के साज-सज्जा के लिए खूबसूरत और आकर्षक हस्तशिल्प के उत्पादों को खरीदा। फेयर में बिहार के कलाकारों की लाखों की कमाई हुई। बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान ने किया।

बिहार के कुशल कारीगरों, बुनकरों और उद्यमियों के सर्वांगीण विकास और उन्हें बड़े पैमाने पर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उद्योग विभाग ने बिहार क्राफ्ट फेयर आयोजित करने की पहल की है। उद्योग विभाग द्वारा बिहार के विभिन्न जिलों में जिला स्तरीय मेले का आयोजन किया जाता आ रहा है। उद्योग विभाग द्वारा अब प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में मेले का आयोजन कर बिहार के कलाकारों को मेले में भाग लेने का मौका दिया जा रहा है। उद्योग विभाग द्वारा चेन्नई और बेंगलुरु में बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन किया गया, जिसे काफी लोकप्रियता मिली। इस फेयर में बिहार के कुशल शिल्पियों, बुनकरों और उद्यमियों द्वारा बनाये गए हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, खादी और ग्रामोद्योग के सामग्रियों की प्रदर्शनी के लिए स्टॉल लगाया गया जो खरीदारी करने के लिए भी उपलब्ध थी। साथ ही इस फेयर में स्टार्ट-अप/मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभार्थी/खाद्य प्रसंस्करण इकाई द्वारा स्टॉल लगाया गया।

कलाकारों द्वारा लाई गई हस्तशिल्प, हथकरघा और खादी की उत्पादों को चेन्नई और बेंगलुरु के लोगों ने खूब सराहा और उन्होंने खूब खरीदारी की। उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने मेले का भ्रमण किया जहाँ उन्होंने बिहार के कलाकारों से मुलाकात की और मेले में स्टॉल लगाने के लिए सभी को बधाई दी। उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार हमेशा से कला और संस्कृति का स्रोत रहा है। बिहार में प्रतिभावान कलाकार हैं जो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं।

बिहार का हस्तशिल्प न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में बहुचर्चित है। ऐसे में सरकार हस्तशिल्प के कलाकारों को हर संभव मदद का प्रयास करती है। बिहार क्राफ्ट फेयर इसी का परिणाम है। पिछले कई महीनों से बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में मेला लगाना सरकार की कोशिश रही है जिसमें शत प्रतिशत सफलता प्राप्त हुई है। माननीय मंत्री ने कहा कि बिहार क्राफ्ट फेयर से बिहार के हुनरमंद शिल्पी न सिर्फ बिहार में बल्कि दूसरे बड़े शहरों में भी अपना हुनर दिखा रहे हैं। खास बात यह है कि बड़े शहरों को यह मेला काफी पसंद आ रहा है। उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार के शिल्पियों, बुनकरों और उद्यमियों को बेहतर मंच देना और उनकी प्रगति के लिए कार्य करना सरकार का उद्देश्य है।

बिहार क्राफ्ट फेयर में लोगों ने जमकर उत्पादों की खरीदारी की और अपने घर के साज-सज्जा के लिए खूबसूरत और आकर्षक हस्तशिल्प के उत्पादों को खरीदा। फेयर में बिहार के कलाकारों की लाखों की कमाई हुई। बिहार क्राफ्ट फेयर का आयोजन उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान ने किया।

मेलों से मिली खादी संस्थाओं को विशेष ताकत

खादी से मिलती है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती: समीर कुमार महासेठ

बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं द्वारा उत्पादित सामग्रियों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रमुख शहरों में खादी मेला का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2022-23 में खादी मेला का आयोजन मोतिहारी, गया, भभुआ, पूर्णिया, आरा तथा सीवान में किया गया है। हर मेले में 100 से अधिक स्टॉल लगाये गये जहाँ खादी संस्थाओं को अपने उत्पाद बेचने का भरपुर मौका मिला।

पूर्णिया में आयोजित खादी मेला में खादी प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ी और डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री पूर्णिया खादी मेले में हुई। इसी तरह मोतिहारी, गया, भभुआ और आरा में आयोजित खादी मेलों में भी खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों की भारी बिक्री हुई जो इस बात का परिचायक है कि आम लोगों में खादी पहनने का रूझान बना हुआ है। इन मेलों में आमलोगों के अलावा राजनीतिक हस्तियों और कलाकारों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।

भभुआ में आयोजित खादी मेला का उद्घाटन बिहार के उद्योग मंत्री श्री समीर कुमार महासेठ ने किया। उद्घाटन समारोह में कैमूर के जिलाधिकारी नवदीप शुक्ल, स्थानीय विधायक भरत बिंद, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी दिलीप कुमार, उप विकास आयुक्त डॉ गजेंद्र कुमार सिंह और प्रसिद्ध हास्य कवि शंकर कैमुरी भी उपस्थित रहे। उद्घाटन के बाद खादी मेला में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि खादी हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है।

महात्मा गांधी ने जब स्वदेशी का आंदोलन चलाया था तो घर-घर में चरखा चलाने का काम हुआ। घर-घर में कुटीर उद्योग प्रारंभ हुए। इससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। लोग स्वाबलंबी हुए। चरखा और खादी से जो ताकत मिली उसी ताकत के बल पर देश आजाद हुआ। प्रदेश के लाखों लोग खादी और ग्रामोद्योग से रोजगार पाते हैं। खादी और कुटीर उद्योगों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली सरकार बिहार के हर युवा को रोजगार देने के लिए संकल्पित है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत हमने 7800 नए उद्यमियों 10- 10 लाख रुपए की सहायता के लिए चयनित किया है। इससे पहले 15000 लोगों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चार-चार लाख रुपए की राशि पहली किस्त के रूप में दी गई। जिन लोगों ने प्रथम किस्त का उपयोग कर लिया

उन्हें दूसरा किस्त भी दे दिया गया है और दूसरे किस्त की उपयोगिता का प्रमाण पत्र देने वाले उद्यमियों को तीसरा किस्त भी दे दिया गया है।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत पिछले 4 महीनों में 1000 से अधिक नए उद्योग खुल चुके हैं। 14000 उद्योग लगाए जाने की प्रक्रिया में हैं। हर उद्योग में 5 से 10 लोगों को रोजगार मिला है। हम चाहते हैं कि बिहार के युवा बिहार में ही काम करें। बिहार में ही उद्योग लगाएं और अपने गांव समाज के दूसरे लोगों को भी रोजगार दें। उद्योग विभाग की हर योजना का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा नए उद्योग स्थापित हों। कैमूर जिला के युवा भी कमर कस लें। विभाग द्वारा उन्हें हर प्रकार की मदद दी जाएगी। खादी मेला और हैंडलूम मेला लगा कर उन्हें मार्केटिंग का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा खादी मॉल के माध्यम से मार्केटिंग में मदद दी जाएगी। उन्होंने युवा उद्यमियों से कहा कि उद्योग के लिए मिलने वाले ऋण को खैरात नहीं समझे।

योजना चाहे जो भी हो, सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता का उपयोग नए उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योगों के विस्तार के लिए करें। जिलाधिकारी नवदीप शुक्ल ने कहा कि कैमूर जिला में उद्योगों की स्थापना के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार कोशिश हो रही है। सभी बैंकों को पीएमईजीपी और पीएमएफएमई जैसे कार्यक्रमों के तहत लक्ष्य के अनुसार ऋण स्वीकृत करने का निर्देश दिया गया है। जो बैंक लक्ष्य के अनुसार ऋण की स्वीकृति नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी दिलीप कुमार ने कहा कि प्रदेश की सभी खादी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए बोर्ड द्वारा सहायता दी जा रही है। भभुआ का खादी मेला भी एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से खादी वस्त्र के उत्पादकों को बाजार मुहैया कराया जा रहा है।

शाजिया क़ैसर
पुराने जूतों को जीवनदान देकर पाई सफलता

वैकल्पिक व्यवसाय की तलाश कर रही शाजिया की नजर सड़क के किनारे काम करने वाले मोचियों पर पड़ी। यहीं से शाजिया को इन्वोवेटिव बिजनेस का नया आइडिया प्राप्त हुआ।

इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ हेल्थ एडुकेशन एण्ड रिसर्च से फिजियोथेरेपी में बैचलर डिग्री ऑर विनायक मिशन यूनिवर्सिटी से हॉस्पीटल और हेल्थकेयर मैनेजमेन्ट में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद शाजिया क़ैसर ने सहजता से चिकित्सा के क्षेत्र में काम करना प्रारंभ किया। पहले वह विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़ी उसके बाद फिजियोथेरेपी क्लिनिक में फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में काम किया और फिर उन्होंने यूनिसेफ के साथ फिजियोथेरेपी कन्सलटेन्ट के रूप में जुड़ गयी। लेकिन वह प्रोफेशन ज्यादा रास नहीं आया तो उन्होंने जीवन में कुछ नया करने का सोंचा।

पैरों को ताकत और सुरक्षा प्रदान करने वाले जूते भी बीमार पड़ सकते हैं ऐसा शायद ही कोई सोंचता हो, लेकिन जब शाजिया क़ैसर ने वैकल्पिक व्यवसाय की तलाश में थी तो उनकी नजर सड़क के किनारे काम करने वाले मोचियों पर पड़ी जो कड़ी धूप और कड़ाके की ठण्ड में भी आजीविका की तलाश में जूतों की मरम्मत करते रहते हैं। यहीं से शाजिया को इन्वोवेटिव बिजनेस का आइडिया प्राप्त हुआ और उन्होंने जूतों का अस्पताल खोलने का निर्णय लिया और उसे रिवाइवल शू-लॉण्ड्री का नाम दिया। बाद में लेदर जैकेट, हैण्ड बैग, ट्रैवलिंग बैग और चमड़े के बने दूसरे उत्पादों के रिपेयरिंग का काम भी रिवाइवल शू-लॉण्ड्री ने प्रारंभ कर दिया।

शाजिया क़ैसर को नये आइडिया पर काम करने के लिए बिहार स्टार्ट-अप नीति के तहत सहायता प्राप्त हुई। उन्हें बिहार इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, अटल इनक्यूवेशन सेन्टर वनस्थली तथा इंडियन एंजेल नेटवर्क से भी स्टार्ट-अप के क्षेत्र में मेन्टरशिप और वित्तीय मदद प्राप्त हुई। उनकी फर्म ने एक शाखा से प्रारंभ करके चार शाखाओं में अपना विस्तार कर लिया है। 2023 में शाजिया बिहार के अलावा तीन दूसरे राज्यों- आन्ध्र प्रदेश, केरल और गुजरात में भी रिवाइवल शू-लॉण्ड्री के विस्तार पर काम कर रही हैं। उनकी योजना है कि वर्ष 2025 तक रिवाइवल शू-लॉण्ड्री का विस्तार देश के सभी प्रमुख शहरों में हो जाए। जूतों को पुनर्जीवन देने के लिए वह जूता का निर्माण करने वाली देश की प्रतिष्ठित कम्पनियों के साथ भी सम्पर्क में हैं। शाजिया ने ग्राहकों को पार्टी, ऑफिस और दूसरे समारोहों में पहनने के लिए कस्टमाइज्ड जूते बनाने के लिए जीया फूडवियर टेलरिंग बूटिक भी खोला है, जो इको फ्रेण्डली तथा अलग-अलग फैब्रिक का इस्तेमाल करके फूटवियर का निर्माण करती है।

शाजिया क़ैसर भारतीय स्टार्ट-अप इको सिस्टम के चमकते चेहरों में एक है। उन्हें बिहार पॉजिटिव अवार्ड सशक्त नारी सम्मान, अपराजिता सम्मान सहित अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। सिविल सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्टार्ट-अप पर रिलीज की गई सक्सेस स्टॉरी पुस्तिका में भी शाजिया क़ैसर को स्थान मिला।

:: अविनाश कुमार झा

फतुहा में बनेगा
मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क

राज्य सरकार द्वारा इसके लिए 100 एकड़ भूमि की अधिग्रहण की योजना बनायी गयी है जिस पर 168.93 करोड़ रुपये का खर्च संभावित है। भूमि अधिग्रहण की लागत 50 प्रतिशत व्यय नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेन्ट लि॰ द्वारा अपने संसाधन से किया जाएगा।

बिहार सरकार के फतुहा में मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण का फैसला लिया है। इस पार्क का निर्माण केन्द्र सरकार की योजना पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 2022-23 के तहत किया जाएगा। इसके लिए चिन्हित भूमि फतुहा अंचल जैतिया मौजा में है।

राज्य सरकार द्वारा इसके लिए 100 एकड़ भूमि की अधिग्रहण की योजना बनायी गयी है जिस पर 168.93 करोड़ रुपये का खर्च संभावित है। भूमि अधिग्रहण की लागत 50 प्रतिशत व्यय नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेन्ट लि॰ द्वारा अपने संसाधन से किया जाएगा।

केन्द्र सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने देश में 35 स्थानों पर मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकास की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के सहयोग से नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजेमेन्ट लि॰ और रेल विकास निगम लि॰ द्वारा उक्त पार्क को विकसित किया जाएगा।

मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का कार्यान्वयन राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच गठित होने वाले स्पेशल पर्पज व्हीक्ल के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें बिहार सरकार की ओर से बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार तथा केन्द्र सरकार की ओर से नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेन्ट लि॰ और रेल विकास निगम लि॰ शामिल रहेंगे।

भारत माला परियोजना के तहत विकसित किये जा रहे इस मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित आगत-निर्गत केन्द्र की स्थापना की जाएगी। इसके तहत रेल, सड़क एवं जलमार्ग परिवहन के द्वारा देश के उत्पादों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमतापूर्वक एवं कम लागत में पहुँचाने का मुख्य प्रयोजन है। मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के विकसित होने पर माल ढुलाई की सुविधा होगी, जिससे सड़क, रेल एवं जलमार्ग जैसी मल्टी-मॉडल परिवहन प्रणाली तक पहुँच होगी और कंटेनर टर्मिनल, कार्गो टर्मिनल, गोदामों, कोल्ड स्टोरेज, मशीनीकृत सामग्री हैंडलिंग के लिए सुविधाएँ विकसित होगी।

मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक पार्क से रेस्त्रं, ड्राइवरों के लिए शयनगृह, कार्यशाला, फ्यूल सेन्टर, इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंग सुविधा केन्द्र, कंटेनर वाशिंग यार्ड, मेडिकल सुविधा केन्द्र, कैन्टीन की सुविधा तथा मनोरंजन पार्क एवं आवश्यक सामग्री की दुकानें विकसित होगी। इस सबके अतिरिक्त बाजार विकसित होगा। नये बाजार उत्पादनों के लिए उपलब्ध होंगे एवं निवेश की नई सम्भावनाएँ विकसित होगी।

हस्तशिल्प की कला को सीख रहे युवा

बिहार की हस्तशिल्प कला को सभी जगह पहचान मिल रही है। ऐसे में इस कला में रुचि रखने वाले और बिहार के पारंपरिक कलाओं के बारे में जानने और उसका प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं के लिए उद्योग विभाग के अंतर्गत उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के द्वारा हस्तशिल्प में निःशुल्क प्रशिक्षण का मौका दिया जाता है जिससे युवा हस्तशिल्प की पौराणिक कला को सीख सकें।

बिहार की हस्तशिल्प कला को सभी जगह पहचान मिल रही है। ऐसे में इस कला में रुचि रखने वाले और बिहार के पारंपरिक कलाओं के बारे में जानने और उसका प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं के लिए उद्योग विभाग के अंतर्गत उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के द्वारा हस्तशिल्प में निःशुल्क प्रशिक्षण का मौका दिया जाता है जिससे युवा हस्तशिल्प की पौराणिक कला को सिख सकें। उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान द्वारा हस्तशिल्प के प्रशिक्षण में युवा बढ़ चढ़ कर प्रशिक्षण लेते हैं जहाँ वे हस्तशिल्प के गुण और इसकी बारीकियों को सीखते हैं। उपेन्द्र महारथी संस्थान में 18 शिल्प कलाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है जो साल में दो बार प्रत्येक छह महीने पर निःशुल्क होता है जिसमें प्रशिक्षण सीखने के लिए सामान भी निःशुल्क मुहैया कराया जाता है। हस्तशिल्प कला की यह निःशुल्क प्रशिक्षण युवाओं को खूब भाता है क्योंकि प्रशिक्षण लेने के बाद वे या तो वे अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं या खुद का स्टार्टअप शुरू करते हैं।

छह महीने का यह प्रशिक्षण आवासीय होता है जहाँ युवाओं को छात्रवास उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे संस्थान में ही रहकर प्रशिक्षण ले सकें। इस प्रशिक्षण में युवा उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण हासिल कर सकें इसके लिए राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हस्तशिल्प के कलाकारों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण मधुबनी पेंटिंग, टिकुली कला, मेटल क्राफ्ट, काष्ठ कला (वुड क्राफ्ट), पेपर मैसी, टेराकोटा, सेरामिक, सिक्की कला, ब्लॉक छपाई, पत्थर कट्टी, चर्म शिल्प, वेणु शिल्प (बैम्बू क्राफ्ट), जूट कला, सूत बुनाई, मंजूषा चित्रकला, गुड़िया शिल्प, एपलिक कला, सुजनी शिल्प कलाओं में दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को बिहार के हस्तशिल्प, इनका इतिहास, इनका

महत्व एवं इनकी जीवन में उपयोगिता के बारे में भी बताया जाता है। हस्तशिल्प में प्रशिक्षण लेने के बाद युवा खुद का कोई व्यवसाय या हस्तशिल्प के क्षेत्र में काम कर सकते हैं जिससे वो अपना जीवनयापन करने में भी सक्षम हो सकेंगे। प्रशिक्षण ले रहे युवाओं का कहना है कि हस्तशिल्प बिहार की लोकप्रिय कला है और इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से सीख भी रहे हैं।

विकास भवन में उद्योग संवाद पत्रिका तथा बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के कैलेंडर का विमोचन करते हुए बिहार के उद्योग मंत्री **श्री समीर कुमार महासेठ** और उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव **श्री संदीप पौण्डरीक**।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों का चयन रेंडमनाइजेशन कंप्यूटराइज पद्धति से करते हुए बिहार के उद्योग मंत्री **श्री समीर कुमार महासेठ**।

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तथा बोर्ड की डायरी का विमोचन करते हुए उद्योग मंत्री **श्री समीर कुमार महासेठ**।

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

दूसरी मंजिल, विकास भवन, पटना, www.industries.bih.nic.in | www.udyog.bihar.gov.in

टॉल फ्री नं : **1800 345 6214**

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के द्वारा प्रकाशित एवं ज्ञान गंगा क्रियेशन्स, पटना द्वारा मुद्रित
वर्ष 5, अंक–11, जनवरी–मार्च, 2023 ● संपादक : दिलीप कुमार